विदेशी कम्पनियों द्वारा नीतिगत नियंत्रण के विरूद्ध सुरक्षोपाय

5953. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संबंधी सरकार की उदार नीति को देखते हुये विदेशी उद्यमियों द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था पर नीतिगत नियंत्रण कर लिये जाने को रोकने के लिये सुरक्षोपाय के रूप में कुछ कदम उठाए गये है अथवा उठाये जाने का विचार है ,

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) . (क) से (ग) भारतीय उद्योग को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना और प्रौद्योगिकीय गत्यात्मकता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिये उपयुक्त वातावरण का सृजन करना नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये अवसरों का पूरा लाभ उठाना भी है जो देश के औद्योगिक विकास के हित में है । विदेशी उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों का परिचालन भी देश के मौजूदा कानून और विनियम के अधीन है ।

Bills pending for enforcement

5954. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

a) the number of Bills passed by Parliament and pending for enforcement as on date;

(b) the Minjstry-wise break-up and since when they are pending;

(c) the reasons for their non-enforcement; and

(d) by when they are likely to become operative?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAj): (a) to d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामले

5955. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की न्यायालय-वार संख्या कितनी थी ;

(ख) इन न्यायालयों में वर्ष 1992 में निपटाये गये मामलों की तुलना में वर्ष 1993 में कितने मामले निपटाये गये .

(ग) वर्ष 1993 में वकीलों द्वारा की गई हड़ताल से न्यायिक प्रकिया पर कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ा ;

(घ) उपर्युक्त इकट्ठे हुये मामलों को निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ङ) सरकार वादियों के सामने आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिये वर्ष 1994 में न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने हेतु क्या उपाय करने का विचार रखती है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31- 2-1993 को मध्य प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले निम्नलिखित थे :-

1. **अधीनस्थ न्यायालय** :

(i) जिला न्यायाधीशों के न्यायालय– 2,22,521

(ii) सिविल न्यायधीशों के न्यायालय– 14,02,408